डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 मार्च, 2021, डिस्पेच दिनांक 16 मार्च, 2021

| वर्ष 64 | अंक 20 | भोपाल | 16 मार्च, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

पशुपालन एवं डेयरी विकास से प्रति वर्ष एक लाख रोजगार सृजित किये जाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा पुशपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्यों को समयबद्ध कार्य–योजना के अनुसार प्राप्त किया जाए। पशुपालन और डेयरी विभाग के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। एक वर्ष में एक लाख लोगों को स्व–रोजगार से जोड़ने की कार्य–योजना तैयार कर उसे अमल में लाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में डेयरी व्यवसाय, पशुपालन विकास, उत्पादन में वृद्धि और विविधीकरण की गतिविधियों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, एम.डी. मध्यप्रदेश दुग्ध संघ श्री शमीम उद्दीन, अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी श्री जे.एन. कंसोटिया मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि मुर्गा–मुर्गी, अण्डे, बकरी और दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए। इस कार्य में प्रदेश को आत्म–निर्भर बनाया जाये। स्व–रोजगार मूलक छोटी–छोटी योजनायें बनायी जाए, जो गरीब परिवारों के लिये आय का जरिया बने और सफलता पूर्वक क्रियान्वित हो। अनेक वर्षों से संचालित हो रही योजनाओं की समीक्षा की जाये तथा अनुपयोगी योजनाओं को बन्द किया जाए। इन योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

कृत्रिम गर्भाधान एवं गोसेवक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ाकर नस्ल सुधार और दूध उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गो–सेवकों को प्रशिक्षित कर और उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदान कर अधिक दक्ष बनाया जाए। बैठक में बताया गया कि कृत्रिम गर्भाधान वर्तमान में 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक का लक्ष्य है। वर्ष 2020–21 में 1628 निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्य में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पशुओं का इलाज

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पशुओं को होने वाली बीमारियों का इलाज अभियान संचालित कर कराये। पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। विलंब से चिकित्सालय आने वाले, अनुपस्थित रहने वाले तथा लापरवाह पशु चिकित्सकों तथा स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। **(शेष पृष्ठ 6 पर)**

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने लगाया आम का पौधा

भोपाल। सहकारिता एवं लोक – सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस के अवसर पर मंत्रालय परिसर में आम का पौधा रोपा। इस अवसर पर मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि पेड़ों से ही हमें प्राण वायु मिलती है, जिसके चलते पृथ्वी के सभी प्राणियों का जीवन संभव होता है।

मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया ने कहा कि निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर लोग वृक्षों को काट देते हैं। हमारे प्रयास होने चाहिए कि वृक्षों को बचाने का संदेश प्रभावी ढंग से प्रसारित हो और लोग स्व–प्रेरणा से पौधरोपण करें। सभी को आगे आकर प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ परिवेश की सौगात मिल सके।

जाँच समिति दो माह में देगी रिपोर्ट

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया के निर्देश पर प्रमुख सचिव सहकारिता द्वारा 4 सदस्यीय जाँच कमेटी का गठन किया गया है। यह जाँच समिति मंदसौर और नीमच जिले में परिवहनकर्ता द्वारा खाद को सोसायटी तक पहुँचाने में की गई हेराफेरी और म.प्र स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन पिपलिया मंडी में भंडारित किए गए उर्वरक की अफरा–तफरी की जाँच करेगी। जाँच कमेटी द्वारा दो माह में जाँच प्रतिवेदन आयुक्त सहकारिता को सौंपा जाएगा।

जाँच कमेटी में म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के महाप्रबंधक श्री एम.के. पाठक, म.प्र. स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के महाप्रबंधक श्री यशपाल, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के उप प्रबंधक श्री अरविंद वर्मा और कलेक्टर मंदसौर एवं नीमच द्वारा नामांकित अधिकारी को शामिल किया गया है।

अपेक्स बैंक में ग्राहकों के लिए यू.पी.आई. सुविधा लागू

भोपाल। यू.पी.आई. (यूनिफाईड पेमेंट इन्टरफेश) की सुविधा अपेक्स बैंक द्वारा 26 फरवरी 2021 को ग्राहकों के लिए शुरू की गई। इस सुविधा से अपेक्स बैंक के खातेदार अब मोबाइल से लेनदेन एवं विभिन्न बिलों का भुगतान भीम एप, पेटीएम एप, फोन पे, गूगल पे आदि के माध्यम से कहीं भी किसी भी समय अपने खाते से कर सकेंगे। साथ ही अपेक्स बैंक के ग्राहक अपने खातों में किसी परिजन/मित्र द्वारा प्रेषित राशि अपने खातों में त्वरित प्राप्त कर सकेंगे और भेज भी सकेंगे। इस सुविधा से अपेक्स बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान ग्राहक की सेवाएँ प्रदान करने की ओर अग्रसर हो गया है। इस तरह की सुविधाएँ भविष्य में जिला बैंकों में भी लागू करने की कार्यवाही की जा रही है।

आत्म निर्भर म.प्र. में कृषि क्षेत्र की होगी महत्वपूर्ण भागीदारी

किसानों के हित में हुए अनेक नवाचार

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के हित में खेती को लाभप्रद बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिये अनेक नवाचार किये हैं। आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन की लागत को कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज को हुए नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना, सरकार के प्रयासों में शामिल हैं।

प्रदेश के किसानों को सरकार से मिल रहे संबल से किसानों ने प्रमुख रूप से गेहूँ उत्पादन में रिकार्ड कायम किया। मध्यप्रदेश गेहूँ उपार्जन में पूरे देश में अव्वल रहा। किसानों के हित में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करते हुए ई–ट्रेडिंग का प्रावधान किया गया और किसानों को उपार्जन केन्द्र के साथ ही मंडी के अधिकृत निजी खरीदी केन्द्र और सौदा–पत्रक व्यवस्था के माध्यम से भी फसल बेचने की सुविधा प्रदान की गई। गेहूँ, धान एवं अन्य फसलों के उपार्जन की 33 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मध्यप्रदेश के किसानों को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष किसानों को 6–6 हजार रूपये दिए जाते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि योजना की शुरूआत कर किसानों को मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रतिवर्ष 4 हजार रूपये दो बराबर किश्तों में दिये जाना शुरू किया गया। इस प्रकार किसानों को अब कुल 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष किसान सम्माननिधि मिल रही है।

प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य परिस्थिति में किसान की उपज को हुए नुकसान में राहत पहुँचाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लंबित प्रीमियम जमा कर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत पहुँचाई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता में आते ही बीमा योजना का लंबित प्रीमियम भरा और प्रभावित किसानों को फसल बीमा राशि दिलवाई गई। लॉकडाउन की विकट स्थिति में एक करोड़ 29 लाख टन गेहूँ 16 लाख किसानों से खरीद कर उनके खातों में 27 हजार करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की गई।

किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण योजना को पुनः चालू करते हुए किसानों को राहत पहुँचाई गई। इसके लिये सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रूपये की राशि भी उपलब्ध करवाई गई, जिससे सहकारी बैंक किसानों को आसानी से कृषि ऋण उपलब्ध करवा सकें।

किसानों की आय को बढ़ाने के लिये बेहतर प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य किया गया। प्रदेश में अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। वर्ष 2020 तक लगभग 40 लाख 27 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएँ विकसित की गईं। प्रदेश में 19 वृहद, 97 मध्यम और 5344 लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया। इसके साथ ही 27 वृहद, 47 मध्यम और 287 लघु सिंचाई योजनाएँ प्रगति पर हैं। प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत मंडला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया एवं सिंगरौली जिलों में 1707 करोड़ की लागत से 24 हजार 364 भू–जल संरचनाओं का निर्माण कर सीमांत एवं लघु किसानों की 62 हजार 133 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित की गई।

कोरोना काल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में 57 हजार 653 जल– संरचनाओं का निर्माण किया गया। इन जल संरचनाओं में रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 1835 करोड़ से अधिक लागत के 1007 स्टॉपडेम, 4467 चेक डेम, 19 हजार कपिल धारा कूप, 2588 सार्वजनिक कूप, 1667 पर्कोलेशन टैंक, 14 हजार 907 हितग्राही मूलक खेत, 2365 सामुदयिक खेत तालाब तथा 4393 नवीन ताबाब बनवाए गए। साथ ही 3115 बावड़ी, तालाब और सामुदायिक जल–संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा सामुदायिक टांका निर्माण सहित 53 हजार 517 जल–संरचनाओं के कार्य किये गये। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 237 करोड़ की लागत से 2697 खेत तालाब, 726 तालाब, 305 परकोलेशन तालाब, 299 चेकडेम, स्टॉप डेम और 109 नाला बंधान के कार्य किये गये। इन सभी जल संरचनाओं से जहाँ एक ओर स्थानीय लोगों को कोरोना काल में रोजगार मिला, वहीं भू–जल स्तर में बढ़ोत्तरी के साथ किसानों को खेती में सिंचाई के लिये पानी भी मिल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा विगत कई वर्षों से सिंचाई बजट में निरंतर वृद्धि भी की जा रही है।

हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रि–परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र में नये प्रावधान जोड़े हैं। इन प्रावधानो में प्राकृतिक प्रकोप, आग लगने तथा वन्य प्राणियों द्वारा मकान नष्ट किये जाने पर आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। इन नये प्रावधानों से प्रदेश के किसानों को भी लाभ मिलेगा। किसानों को कृषि कार्य के लिये फ्लैट दरों पर बिजली दी जा रही है, जिसमें 22 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। किसानों को खेती के लिये बिजली कनेक्शनों पर 14 हजार 244 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया।

कृषि अधोसंरचना विकास फंड में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। अधोसंरचना विकास के लिये आत्म–निर्भर कृषि मिशन का गठन किया गया है। पिछले 10 माह में कृषि विकास एवं किसान–कल्याण के लिये विभिन्न योजनाओं पर 83 हजार करोड़ रूपये से अधिक के हितलाभ दिये गये हैं। किसानों के हित में मंड़ी नियमों में ऐतिहासिक सुधार भी किया गया हैं। मंडी टेक्स 1.50 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत किया गया। कृषि की लागत कम करने, उपादन बढ़ाने तथा उपज का सही दाम किसानों के दिलाने के लिए कृषि उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) को मजबूत किया जा रहा है। आगामी वर्षों मे एक हजार नये कृषि उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा।

सरकार द्वारा किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5 हजार रूपये की गई है। इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन भी किया गया है।

प्रदेश के किसानों को उत्तम गुणवत्ता के खाद–बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस वर्ष किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराए जाने के बाद यूरिया का सरप्लस भण्डारण रहा। नकली खाद–बीज बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निलंबित और निरस्त भी किए।

किसानों को उन्नत तकनीकी के साथ औषधीय खेती के लिए प्रोत्साहित करें : मंत्री डॉ. मिश्रा

भोपाल। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने किसानों से कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से कृषि की उन्नत एवं आधुनिक तकनीकी की जानकारी प्राप्त करें। कृषि विज्ञान केन्द्र की भी जबावदारी है कि केन्द्र के कृषि वैज्ञानिक एवं अधिकारी गाँव–गाँव में जाकर किसानों को परम्परागत फसलों के साथ औषधीय पौधों की खेती के रूप में सफेद मूसली, अश्वगंधा एवं मशरूम आदि फसले लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, जिससे खेती लाभ का धंधा बन सके।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा शनिवार को कृषि विज्ञान केन्द्र दतिया में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत् किसान संगोष्ठी एवं बीज भण्ड़ार के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने इस मौके पर कृषकों का सम्मान कर कृषि उपकरण प्रदाय किए।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि 12 वर्ष पूर्व दतिया कृषि उपज मंडी में गेंहूँ दो हजार क्विंटल आता था जो अब बड़कर 50 हजार क्विंटल हो गया है। जबकि धान की आवक 60 से 70 हजार क्विंटल हो गई है। इसके पीछे कृषि की आधुनिक पद्धति के साथ किसानों की मेहनत एवं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह रही है। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यो का मूल्यांकन कर उत्कृष्ट पाए जाने पर दतिया का केन्द्र देश में प्रथम स्थान पर रहा है। यह केन्द्र मध्यप्रदेश के सबसे अच्छे केन्द्रों में से एक है।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों से कहा कि किसानों को केन्द्र पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देने के साथ गांव–गांव में जाकर शिविर एवं संगोष्ठियों के माध्यम से कम लागत में अधिक उत्पादन लेने तथा किसानों की आय दोगुनी करने तथा खेती लाभ का धंधा बने इसके लिए कृषकों को जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि कृषकों को परम्परागत फसलों के साथ फलोद्यान, फ्लोरीकल्चर, औषधीय पौधों की खेती के रूप में सफेद मूसली, अश्वगंधा की खेती लेने के लिए भी प्रेरित करना होगा। औषधीय खेती की मांग को देखते हुए किसानों को इस दिशा में रूझान बढ़ाना होगा। मंत्री डॉ. मिश्रा ने किसानों से कहा कि वह सब्जी की खेती के रूप में ब्रोकली एवं मशरूम की खेती करें। इस खेती से अन्य सब्जियों की अपेक्षा अधिक दाम प्राप्त कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक इन सब्जियों के उत्पादन के लिए तकनीकी सलाह देकर कृषकों को भी प्रेरित करें।

100 करोड़ की लागत से नारी सम्मान कोष स्थापित होगा

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सौगातों की बौछार

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह रस्म अदायगी नहीं है। नारी उत्थान। मेरी जिन्दगी का मिशन है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउण्ड पर महिला सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम **''नारी तू नारायणी''** में कही। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो नारी न कर सके। मुख्यमंत्री ने आज महिलाओं, विशेष रूप से महिला स्व–सहायता समूह के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी महिलाओं का अभिवादन किया। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री सुश्री मीना सिंह, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामखेलावन पटेल भी उपस्थित थे।

स्व–सहायता समूहों को 4 की जगह 2 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा ऋण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज स्व–सहायता समूहों के खातों में 200 करोड़ रूपये डाले गए हैं। अब हर माह इनके खाते में 150 करोड़ रूपये डाले जाते रहेंगे। उन्होंने स्व–सहायता समूहों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समूह ऋण का एक–एक रूपया बैंकों को वापस चुकाते हैं। अब स्व–सहायता समूहों को 4 प्रतिशत ब्याज की जगह 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाएगा, बाकी ब्याज सरकार वहन करेगी।

देश–विदेश में लाड़ली लक्ष्मी की उच्च शिक्षा का खर्च वहन करेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के मान–सम्मान बढ़ाने के प्रयास होंगे। कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं के बच्चों के लिए उमंग कार्यक्रम लागू होगा। इसमें लड़कों को लड़कियों के प्रति इज्जत देने के संस्कार दिए जाएंगे। पुरूष प्रधान मानसिकता को बदलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा आज प्रदेश में 38 लाख लाड़ली लक्ष्मी हैं। आई.आई.टी., आई.आई.एम, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग सहित देश–विदेश में इनकी उच्च शिक्षा की फीस सरकार वहन करेगी। सौ करोड़ रूपये की लागत से नारी सम्मान कोष स्थापित होगा। छात्राओं की कॅरियर काउंसलिंग होगी।

घर की महिला सदस्यों के नाम रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी 2 प्रतिशत की छूट

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जमीन में पति के साथ पत्नी का नाम जोड़ना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि नई सम्पत्ति बहन, माँ, बेटी, पत्नी के नाम पर खरीदने पर रजिस्ट्रेशन में दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आवास योजनाओं में पति–पत्नी दोनों का नाम होगा। चाबी संयुक्त रूप से दी जाएगी।

संविदाकर्मी महिलाओं को मिलेगा 180 दिन का प्रसूति अवकाश

प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में वूमेन हेल्प डेस्क अलग से खोली जाएगी। संविदा कर्मी महिलाओं को भी अब 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलेगा। संबल योजना की लाभार्थी महिलाओं को दो बच्चों के जन्म पर प्रसव के पहले 4 हजार रूपए और जन्म के बाद 12 हजार यानी 16 हजार रूपए दिए जाएंगे ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। श्री चौहान ने कहा कि ऐसे गाँवों को विकास के लिए 2 लाख रूपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी, जहाँ बेटे और बेटी की संख्या लगातार तीन वर्ष बराबर रहती है। सभी जिलों में महिला थाना सुनिश्चित किए जाएंगे। प्रदेश के 1600 स्वास्थ्य केन्द्र आधुनिक केन्द्र बनेंगे। प्रसूति सुविधाओं का विस्तार होगा। नगरीय निकायों में कार्यरत अस्थाई महिला सफाई कर्मियों को भी सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलेगा।

गाँव के हर घर पहुँचेगा नल–जल

मुख्यमंत्री ने कहा आने वाले तीन सालों में हर गाँव के हर घर में नल–जल मिलेगा। इस साल बजट में 6 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाकर 26 लाख घरों में नल–जल देने का लक्ष्य है। केन्द्र सरकार से भी राशि मिलेगी। तीन वर्ष में एक करोड़ 3 लाख घरों में नल–जल सुविधा पहुँचाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंचायतों में नारी अदालत स्थापित होगी। इससे परिवारों में होने वाले छोटे–मोटे झगड़े थाने और अदालत तक न पहुँचकर घर पर ही सुलझ जाएंगे।

बेटियों को बरगलाने वालों को मिलेगा आजीवन कारावास

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक प्रस्तुत किया गया है। डरा, धमकाकर, बहला–फुसलाकर बेटियों को बरगलाने वाले अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। उन्होंने मध्यप्रदेश पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुलिस ने ऐसी 9 हजार लापता बेटियों को ढूँढ निकाला है। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने न केवल दुराचार करने वाले अपराधियों को फाँसी की सजा का प्रावधान किया बल्कि अब तक 72 ऐसे नर पिशाचों को फाँसी दी जा चुकी है। श्री चौहान ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील करते हुए कहा कि अक्सर निम्न स्तरीय अदालत से होते हुए सर्वोच्च अदालत तक पहुँचने में बहुत विलंब हो जाता है इसलिए जल्द से जल्द सुनवाई के नए दिशा–निर्देश जारी किए जाए, ताकि फैसला जल्दी हो।

स्व–सहायता समूहों को मिलेंगी अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गेहूँ और अन्य फसलों की खरीदी भी अब महिला स्व–सहायता समूह करेंगे, जिसमें उनको कमीशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन में प्रयुक्त तेल, मसाले आदि की खरीदी भी महिला स्व–सहायता समूह से की जाएगी। पंचायत स्तर पर होने वाले सर्वेक्षणों में महिला स्व–सहायता समूहों को शामिल किया जाएगा। मनरेगा के तहत 50 प्रतिशत मेट महिला स्व–सहायता समूह की सदस्य होंगी। अभी यह 23 प्रतिशत है। शासकीय स्कूलों के बच्चों की यूनिफार्म महिला स्व–सहायता समूह ही सिलेंगे। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकल को वोकल बनाने की बात कही है। प्रदेश में स्व–सहायता समूहों के माध्यम से लोकल को वोकल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 10 महिला समूहों से जीवंत संवाद भी किया।

नशा मुक्ति अभियान में स्व–सहायता समूह जुड़ेंगे

प्रदेश को अभियान चलाकर नशा मुक्त बनाया जाएगा। इसमें महिला स्व–सहायता समूहों की सशक्त भागीदारी होगी। पूर्ण रूप से नशा मुक्त पंचायतों को पुरस्कृत करने के साथ अलग से विकास के लिए राशि भी दी जाएगी। आत्म–रक्षा के लिए बेटियों के लिए आज से अपराजिता कार्यक्रम लागू किया गया है। इसमें प्रदेश की 23 हजार छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की रही उपस्थिति

मंच पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की भी उपस्थिति रही। इनमें पदमश्री भूरी बाई, सीधी बस दुर्घटना में साहस का परिचय देकर कई लोगों की जान बचाने वाली सुश्री शिवरानी, डॉ. गीता रानी गुप्ता, सुश्री कंचन वर्मा, सुश्री द्रोपदी चौकसे, सुश्री ज्योति गौर, सुश्री मनीषा कीर, सुश्री रेवती पटेल, सुश्री अनादी, सुश्री पूनम श्रोती शामिल हैं।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्या पूजन से किया। संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने स्वागत भाषण और जनजातीय कार्य विभाग मंत्री सुश्री मीना सिंह ने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर स्व–सहायता समूह पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के अधिकांश जिलों के स्व–सहायता समूह वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े थे, जिनसे मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया।

किसानों के हित में तीन विभाग मिलकर बनाएंगे संयुक्त कार्य योजना

भोपाल। किसानों की आय को दोगुना करने के लिये किसानों से जुड़े राज्य शासन के तीन विभाग खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, सहकारिता और किसान कल्याण तथा कृषि कल्याण विकास विभाग रोडमेप के अनुसार एक संयुक्त कार्य–योजना बनाकर काम करेंगे। इस उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल एवं सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने मंत्रालय में सोमवार को संयुक्त बैठक की। सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि किसानों के हित में संयुक्त रूप से कियें गये प्रयासों के समुचित परिणाम सामने आएंगे, जो आत्म– निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में मील के पत्थर साबित होंगे। खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि गेहूँ, चना एवं मसूर की खरीदी के लिये किसानों का ई–पोर्टल पर पंजीयन का काम पूरा हो चुका है। अब उन्हें गेहूँ खरीदी के लिये एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप इस वर्ष भी पंजीकृत किसानों से गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसों की रिकार्ड खरीदी की जाएगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों की भलाई एवं उनकी उन्नति के लिये कृषि से जुड़े कृषि, सहकारिता एवं खाद्य विभाग की महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका है। किसानों के लाभ के लिये सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कार्य–योजना बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।

13 लाख 80 हजार विद्यार्थियों के खाते में 326 करोड़ 25 लाख से अधिक की राशि अंतरित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सिंगल क्लिक से जारी की राशि

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा छठवीं से व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है। प्रदेश में 20 से 25 किलोमीटर की परिधि में सी.एम.राइज़ स्कूल आरंभ किये जाएगें, जिनमें प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था होगी। आस–पास के क्षेत्रों से विद्यार्थियों को लाने–ले–जाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े प्रदेश की सभी शालाओं के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे।

मंत्रालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक के 13 लाख 80 हजार से अधिक छात्र–छात्राओं के खाते में सिंगल क्लिक से 326 करोड़ 25 लाख से अधिक की राशि अंतरित की गई। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामखेलावन पटेल उपस्थित थे।

कोरोना काल में शिक्षकों की भूमिका सराहनी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार शिक्षा के उद्देश्य हैं। इससे हम पीढ़ियों से संचित ज्ञान परम्परा से लाभान्वित होते हैं। कौशल हमें आजीविका के प्रबंधन के योग्य बनाता है और नागरिकता के संस्कार से ईमानदारी, परिश्रम, कर्त्तव्य निष्ठा, चारित्रिक बल तथा देशभक्ति के गुण विकसित होते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता के लिए संकल्पित होकर लक्ष्य तय कर परिश्रम आवश्यक है। परीक्षा में उत्साह से भरे रहें पर तनाव न पालें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना काल की कठिन परिस्तिथियों में शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया से निरन्तर विद्यार्थियों की शैक्षिणक कठिनाइयों को दूर करने के प्रयासों की सराहना की।

27 प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण

समेकित छात्रवृत्ति योजना में पाँच विभागों की 27 प्रकार की छात्रवृत्तियों की 326 करोड़ 25 लाख से अधिक की राशि 13 लाख 80 हजार से अधिक छात्र–छात्राओं के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की गई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 1 लाख 30 हजार 628 विद्यार्थी, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के 4 लाख 78 हजार 825, जनजातीय कार्य विभाग के 4 लाख 32 हजार 484, विमुक्त, घुम्मकड़ एवं अर्धघुम्मकड़ जनजातीय कल्याण विभाग के 2 हजार 896 और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 3 लाख 35 हजार 413 विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान का विद्यार्थियों से संवाद

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम में जिलों से सम्मलित हो रहे छात्र–छात्राओं से वर्चुअल संवाद भी किया। झाबुआ के पीपल कोटा गाँव की कुमारी रीना ने कहा कि वह डॉक्टर बन समाज–सेवा करना चाहती हैं।, मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोरोना काल के अनुभवों के बारे में पूछने पर कटनी के श्री ओमप्रकाश ने बताया कि वह एनडीए की तैयारी कर सेना में जाना चाहते है। बालाघाट की कुमारी करीना ने संस्कृत श्लोक के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना संकल्प बताते हुए कहा कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मात्र इच्छा से नहीं। वह सिविल सर्विस को अपना कैरियर बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कुमारी करीना से कहा कि प्रथम पंक्ति में आना है तो मेहनत करनी होगी। शिवपुरी के आकाश शिवहरे, दमोह के अर्जुन मुंडा और संजना गोंड से भी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बात–चीत की। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण श्रीमती पल्लवी जैन गोविल और आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत उपस्थित थी।

प्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी को तीन साल में मिलेगा नल से जल

ग्वालियर। जल प्रत्येक जीव के जीवन की पहली जरूरत है। राज्य सरकार भी इसे अपनी प्राथमिकता में रखते हुए इसकी शीघ्र उपलब्धता और बेहतर प्रबंधन को निरंतरता दे रही है। प्रदेश के ग्रामीण अंचल में हर परिवार को घर में ही नल कनेक्शन से पानी उपलब्ध करवाये जाने से माताओं–बहनों को पानी के लिए नदी, तालाब, कुँआ अथवा बावड़ी तक जाने से निजात मिल जायेगी। राज्य सरकार के ग्रामीण आबादी को नल से जल मुहैय्या करवाने के कारगर प्रयासों से अब किसी को "नीर के लिये पीर" नहीं सहना होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से घोषणा की थी कि देश की समूची ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उनके घर पर ही नल कनेक्शन के जरिये दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इसके बाद भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने ''राष्ट्रीय जल जीवन मिशन'' की गाइड लाइन जारी की। मिशन के मुताबिक गाँव के हर परिवार को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने पर होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देगी तथा 50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार को वहन करना है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की करीब सवा 5 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के जरिये गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध करवाने के लिये "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत कार्यवाही के निर्देश दिये। इससे प्रदेश में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को जल जीवन मिशन से मिली गति और ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन। मिशन के जरिये दिसंबर 2020 तक 30 लाख से ज्यादा नल कनेक्शन दिये गये हैं। इससे 1473 ग्राम शत–प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन युक्त हो चुके हैं।

मिशन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री के सभी स्कूलों, आँगनवाड़ियों में नल कलेक्शन से पेयजल प्रदान करने के 100 दिवसीय अभियान में प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक 12 हजार 881 शालाओं तथा 6 हजार 284 आँगनवाड़ियों में नल से जल सुलभ कराया जा चुका है। शेष स्कूल और आँगनवाड़ियों में 31 मार्च 2021 तक नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम प्रदेश के सभी ग्रामीण अंचल के हर परिवार तक नल कनेक्शन से जल पहुँचाने के लिये लगातार कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाने के लिए 13 हजार 530 करोड़ की लागत की एकल और समूह जलप्रदाय योजनाओं पर कार्य जारी है। इनके पूर्ण होने पर 44 लाख 56 हजार नल कनेक्शन दिए जायेंगे, जिससे लगभग साढ़े 18 हजार ग्राम शत–प्रतिशत FHTC युक्त हो जायेंगे। जल जीवन मिशन में जल–संरचनाओं के निर्माण और संधारण के कार्य लगभग हर जिले में जारी हैं। ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जलप्रदाय योजनाओं की स्वीकृति दिए जाने का सिलसिला बना हुआ है।

खेती संबंधी बंटाई अनुबंध की कॉपी तहसीलदार को देना अनिवार्य

भोपाल। सामान्य तौर से कृषकों और भू–स्वामियों द्वारा अपनी भूमि अन्य व्यक्तियों को देकर खेती कराई जाती है। जिसे सामान्य तौर पर बंटाई, सिकमी, अन्य स्थानीय नामों से जाना जाता है। तत्संबंध में मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बंटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अनुरूप भूमि बंटाई पर दिए जाने की मान्यता प्रदान की गई है। हित संरक्षण अधिनियम भूमि स्वामी एवं बंटाईदार दोनों के हितों का संरक्षण करता है। अब कोई भी भूमि स्वामी अपनी भूमि बटाई पर देने या किसी व्यक्ति द्वारा बटाई पर लेने की वैधानिकता तभी मानी जाएगी, जब दोनों पक्षों के द्वारा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी बंटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के नियम चार के तहत अनुबंध निष्पादित किया गया हो और एक प्रति संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को उपलब्ध कराई हो। कोई भी बंटाईदार, भूमि बंटाई पर लेकर यदि वह फसल क्षति की देय राहत राशि, बीमा राशि और कृषि उपज का उपार्जन के लिए दावा करता है, तो शासन द्वारा तभी स्वीकार माना जाएगा जब भूमि स्वामी और बंटाईदार के मध्य उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध निष्पादित हुआ हो अन्यथा विधिवत अनुबंध के अभाव में उपरोक्त हित लाभ दिया जाना संभव नही होगा।

पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तन

भोपाल। राज्य शासन ने पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तित कर पशुपालन एवं डेयरी विभाग कर दिया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 11 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

शिकायतों के निवारण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करें : मुख्यमंत्री

समाधान ऑनलाइन में सुलझाई गई जन–समस्याएँ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हितग्राहियों को प्रो–एक्टिव होकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाये। आवेदनों का निराकरण समय–सीमा में हो और सी.एम. हेल्पलाइन 181 में दर्ज प्रकरणों का निराकरण किये बिना उन्हें फोर्स क्लोज नहीं किया जाये। लापरवाह अधिकारियों–कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य में उच्च प्रदर्शन करने वाले विभागों, जिलों और अधिकारियों को बधाई दी। वहीं निम्न प्रदर्शन पर कार्य में सुधार लाने की चेतावनी भी दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतों का ऑनलाइन निराकरण कर रहे थे। वी.सी. में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी मौजूद थे।

हितग्राही को योजना का लाभ दिलाने प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाए

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी जिले के हितग्राही श्री गणेश किरार के प्रकरण में निर्देश दिये कि जिला प्रशासन प्रो–एक्टिव होकर योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ दिलाये। आवेदक ने निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन किया था। दो वर्ष तक आवेदन का निराकरण नहीं हुआ। अब उन्हें योजना का लाभ मिल गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने देरी के लिये जिम्मेदार अधिकारी–कर्मचारियों से जवाब मंगाने तथा कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

पेयजल योजनाओं का लाभ दिलाये

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी जिले के श्री मनोहर राजपूत के आवेदन के निराकरण के संबंध में निर्देश दिये कि तकनीकी कारणों से बंद शहरी–ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्रीष्म ऋतु आने के पहले चिन्हांकित कर नागरिकों को सुगमता से पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

आवेदक ने शिकायत की थी कि उसके घर नल–जल योजना का जल नहीं पहुँच रहा है। शिकायत को फोर्स क्लोज कर दिया गया था। पुनः आवेदन के पश्चात प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है।

लापता बालिका को खोज कर लाया गया

दतिया जिले के श्री सुमित शाक्य ने बताया कि उनके परिवार की एक बालिका लापता थी। पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में यह मामला आने पर पुलिस की सक्रियता बढ़ायी गयी तथा बालिका को ढूँढ कर लाया गया।

हितग्राही को योजना की जानकारी दें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खण्डवा के श्री अमृत रक्षय के मामले में निर्देश दिये कि हितग्राही को योजना के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिये ताकि योजना के संबंध में कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहे। आवेदक ने शिकायत की थी कि उसे रेशम विभाग की योजना की किस्त समय पर नहीं मिली। बताया गया कि उन्हें किस्ते समय पर मिल रही थी। उन्हें योजना के संबंध में पूरी जानकारी नहीं थी।

डाक खर्च नहीं लिया जाये

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जबलपुर जिले के मोहम्मद अनवर हुसैन के आवेदन के संबंध में निर्देश दिये कि यदि कोई छात्र उपाधि लेने विश्वविद्यालय के कार्यालय स्वयं आता है तो उसे उपाधि देते हुए पोस्टल चार्ज नहीं लिया जाये। उपाधि यदि डाक के माध्यम से भेजी जाती है तो ही डाक खर्च लिया जाये। आवेदक ने एल.एल.बी. की उपाधि के लिये आवेदन दिया था, लेकिन नियमानुसार पोस्टल शुल्क जमा नहीं करने पर उपाधि नहीं मिल रही थी। अब उन्हें उपाधि मिल गयी है।

जाति प्रमाण–पत्र देने में विलंब पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आवेदक श्री भगतराम धुर्वे को जाति प्रमाण–पत्र देने में विलंब होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये। आवेदक को जाति प्रमाण–पत्र मिल गया है।

वेतन समय पर मिले

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने देवास जिले में जनपद पंचायत में कार्यरत चौकीदार श्री तकत सिंह को 26 माहों का वेतन नहीं मिलने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए। ऐसे सभी प्रकरणों की समीक्षा की जाये तथा वित्त विभाग से जरूरी बजट आवंटन प्राप्त कर समय पर वेतन देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में यह मामला आने के बाद आवेदक को वेतन मिलने लगा है।

बैंक खाता नंबर गलत होने से नहीं मिली राशि

रायसेन के श्री अभिषेक रघुवंशी को छात्रवृत्ति राशि, सतना के श्री आलोक पाण्डे को उर्वरक ऋण की राशि, दमोह के श्री अनिकेत सेन लोधी को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति राशि और रीवा के श्री उमाकांत वर्मा को तेन्दूपत्ता तोड़ने की पारिश्रमिक राशि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाता नंबर गलत होने के कारण समय पर राशि अंतरित नहीं हो सकी। सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत होने पर प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई कर खाता नंबर में सुधार कर राशि उनके खाते में अंतरित कर दी गयी है।

उच्च एवं निम्न प्रदर्शन वाले विभाग

शिकायतों के निराकरण में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परिवहन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, महिला–बाल विकास, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रदर्शन उच्च रहा। वहीं उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण, चिकित्सा शिक्षा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, सहकारिता, कुटीर एवं ग्रामोद्योग और नर्मदा घाटी विकास विभाग को शिकायतों के निराकरण में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये।

उच्च एवं निम्न प्रदर्शन वाले जिले

शिकायतों के निराकरण में सिवनी, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, सिंगरौली, छतरपुर, बुरहानपुर, निवाड़ी, होशंगाबाद, अलीराजपुर और डिण्डौरी जिलों का प्रदर्शन उच्च रहा। भिण्ड, सागर, कटनी, पन्ना और सीधी जिलों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये।

रैंक में सुधार

आवेदनों के निराकरण में दतिया, आगर–मालवा, विदिशा, अलीराजपुर और शिवपुरी जिलों की रैंक में सर्वाधिक सुधार दर्ज किया गया।

पुलिस प्रदर्शन

पुलिस और यातायात विभाग के अंतर्गत सतना, छिंदवाड़ा, अशोकनगर, पन्ना और आगर–मालवा जिलों में उच्च प्रदर्शन दर्ज किया गया है।

उच्च प्रदर्शन वाले अधिकारियों को बधाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिकायत निवारण तथा आवेदनों के निराकरण में उच्च प्रदर्शन करने वाले जबलपुर जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री प्रभाष राज घनघोरिया, टीकमगढ़ जिले के जिला रोजगार अधिकारी श्री एल. पी. लाडिया, छतरपुर जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री श्री अजीत मंसूरी, होशंगाबाद जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राम सोनी तथा सतना जिले में जिला परिवहन अधिकारी श्री संजय श्रीवास्तव को बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने म्युनिस्पिल परफार्मेंस इण्डेक्स में प्रथम आने पर इंदौर जिले के अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने म.प्र. पुलिस को क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेसिंग नेटवर्क सिस्टम के क्रियान्वयन में इस माह देश में प्रथम आने पर भी बधाई दी।

आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित

भोपाल। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के आधार पर आदिम जाति कल्याण विभाग के स्थान पर विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया गया है। इस संबंध में आयुक्त जनजातीय कार्य ने प्रदेश के समस्त कमिश्नर, कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन आधिकारी जिला पंचायत को परिवर्तित नाम से पत्र व्यवहार करने के निर्देश जारी किए है।

इस संबंध में विभाग के संभागीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त और जिला संयोजक को भी परिवर्तित नाम से पत्र व्यवहार करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

विकास कार्यों के लिये एक करोड़ रूपये से अधिक के कार्यों की मंजूरी

जनजातीय कार्य विभाग ने जनजातीय क्षेत्रों में 8 विकास कार्यों के लिये एक करोड़ 20 लाख रूपये की मंजूरी दी है। यह कार्य सीधी एवं उमरिया जिले में मंजूर किये गये हैं। मंजूर किये गये कामों में सामुदायिक भवन निर्माण और हायर सेकेण्डरी स्कूल के बाउण्ड्री बाल के निर्माण कार्य प्रमुख हैं। विभाग ने निर्माण एजेंसियों को मंजूर कामों को गुणवत्ता के साथ नियत समय–सीमा में पूरा किये जाने के निर्देश दिये हैं।

किसानों की मेहनत मध्यप्रदेश को फिर बनाएगी सिरमौर : मुख्यमंत्री

गेहूँ उपार्जन, परिवहन और भंडारण की अग्रिम व्यवस्थाएँ हुई

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस बार पुनः मध्यप्रदेश के किसानों की मेहनत रंग लाएगी और गेहूँ उपार्जन में प्रदेश पुनरू देश में अव्वल होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारे अन्नदाता किसानों को राज्य सरकार हरसंभव मदद कर रही है। रबी विपणन 2021–22 में किसानों की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिये पुख्ता इंतजाम किये जा चुके हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज का विक्रय करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इस वर्ष भी ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन

किसानों की सहूलियत के लिये इस बार भी ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की व्यवस्था की गई है। पोर्टल पर अभी तक 21 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। पंजीयन का कार्य प्रदेश के 3518 केन्द्रों पर किया गया है। साथ ही गिरदावरी किसान एप, कॉमन सर्विस सेंटर और कियोस्क केन्द्रों पर भी किसानों को पंजीयन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उपार्जन व्यवस्थाओं में यह प्रयास भी किया गया कि कोई भी किसान पंजीयन से वंचित न रहे।

कुल 4500 केन्द्रों पर होगी गेहूँ खरीदी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष भी प्रदेश के 4500 खरीदी केन्द्रों पर गेहूँ उपार्जन का कार्य किया जाएगा। खरीदी कार्य में स्व–सहायता समूहों, एफपीयू और एफपीसी को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी के साथ उसके भंडारण और परिवहन की पुख्ता व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। उपार्जन केन्द्रों पर गेहूँ खरीदी का कार्य मार्च माह से शुरू किया जाएगा। इसके लिये तय किया गया है कि इंदौर और उज्जैन में 22 मार्च से और शेष अन्य जिलों में एक अप्रैल से गेहूँ उपार्जन शुरू किया जाएगा। इस वर्ष लगभग एक करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और 20 लाख मीट्रिक टन दलहन एवं तिलहन उपार्जन का अनुमान है। उपार्जित स्कन्धों के शीघ्र परिवहन एवं भंडार की व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जा रही हैं।

गेहूँ उपार्जन में प्रदेश का कीर्तिमान किसानों की बदौलत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर एक करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का जो इतिहास रचा गया, उसके मूल में किसानों की कड़ी मेहनत है। प्रदेश के किसानों ने मध्यप्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा भी हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के इतिहास में समर्थन मूल्य पर हुई रिकार्ड खरीदी में सरकार द्वारा की गई चाक–चौबंद व्यवस्थाओं ने भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाई।

कृषि क्षेत्र में किये गये हैं अनेक नवाचार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका है। कृषि क्षेत्र में आत्म–निर्भरता के लिये प्रदेश के किसानों के हित में खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिये अनेक नवाचार किये गये हैं। राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कृषि का उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत कम हो और किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के दौरान किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की पर्याप्त क्षतिपूर्ति हो सके, इसके लिये प्रावधानों में संशोधन भी किया गया है।

खाद, बीज के साथ सिंचाई और बिजली की व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को समय पर खाद–बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए सिंचाई के लिये पानी और बिजली की व्यवस्थाएँ की गई हैं। कोरोना काल में जब सभी गतिविधियाँ प्रायरू बंद हो रही थी, उस समय विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से जल–संरचनाओं का निर्माण करवाया गया। इससे जहाँ एक ओर स्थानीय लोगों को कोरोना काल में रोजगार मिला, वहीं दूसरी ओर भू–जल स्तर में बढ़ोत्तरी होने से किसानों को सिंचाई के लिये पानी की सहज उपलब्धता भी सुनिश्चित हुई। प्रदेश में बड़ी एवं लघु सिंचाई योजनाओं पर भी युद्ध स्तर पर कार्य हुआ, जिसका लाभ किसानों को मिला।

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि

किसानों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी शुरू की गई। इस योजना में अब तक 57 लाख 50 हजार से अधिक पात्र किसानों को दो–दो हजार के मान से लगभग 1150 करोड़ रूपये का भुगतान ऑनलाईन किया गया है। इसके अलावा किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ भी प्रतिवर्ष प्रति किसान 6 हजार रूपये पूर्व से प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं के नाम से किसानों के साथ छल करने वाले व्यवसायियों पर भी कड़ी कार्यवाहियाँ की गई हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश में नकली खाद, बीज और दवाओं का विक्रय न हो।

(पृष्ठ 1 का शेष)

पशुपालन एवं डेयरी विकास....

फ्रोजेन सीमेन

फ्रोजेन सीमेन के 26 लाख सीमेन डोजेस का उत्पादन किया गया है। इसे बढ़कार 45 लाख फ्रोजेन सीमेन डोजेस का लक्ष्य हासिल किया जायेगा।

पशु टीकाकरण

बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में करीब 253 लाख पशुओं में एफ.एम.डी. टीकाकरण किया गया है। पशुओं की 12 बीमारियों के लिये वैक्सीन बनाने वाली महू स्थित जैविक उत्पाद प्रयोगशाला का उन्नयन एवं नवीनीकरण किया जायेगा।

परियोजनायें

बताया गया कि भोपाल में 12 करोड़ रूपये की प्रोडेक्ट डेयरी परियोजना, इंदौर में 5 करोड़ रूपये लागत की मक्खन भण्डारण के लिये कोल्डस्टोरेज परियोजना और रीवा में 3 करोड़ 50 लाख रूपये लागत के 20 हजार लीटर क्षमता के दुग्ध संयंत्र स्थापना परियोजना को स्वीकृत किया गया है।

गौशालायें

वर्ष 2019–20 में 1004 गोशालायें स्वीकृत की गयी, जिनमें से 963 गौशाओं का निर्माण पूरा हो गया है। वर्ष 2020–21 में 2365 गौशाला निर्माण का लक्ष्य है।

डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम

बैठक में निर्णय लिया गया कि नाना जी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अंतर्गत डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेगें। प्रथम चरण में दो स्थानों पर यह पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा।

विज्ञान केन्द्र

पशुपालन एवं डेयरी गतिविधियों के विस्तार के लिये कृषि विभाग अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों को ही पाठ्यक्रम एवं डेयरी विकास की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी।

पशुपालनों को किसान क्रेडिड कार्ड

पशुपालन अंतर्गत तीन लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिड कार्ड प्रदान करने के लक्ष्य के विरूद्ध बैंकों को 4 लाख आवेदन प्रस्तुत किये गये है। वर्तमान में 84 हजार किसान क्रेडिड कार्ड स्वीकृत किये जा चुके है।

बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान की शुरूआत

जिला सिवनी में पायलट आधार पर बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा शुरू की गयी है।

मध्यप्रदेश की प्रगति का नया इतिहास बनाएंगे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रियों को किया संबोधित

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य एक जुनून और जज्बा है। इसके जरिये हम मध्यप्रदेश की प्रगति का नया इतिहास बनाएंगे। हमें अपने प्रयासों में सफलता अवश्य मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में मंत्रि–परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रीगण से पूर्व में निर्धारित किए गए शेड्यूल के अनुसार प्रति सोमवार को अपने विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि सोमवार और मंगलवार को राजधानी में रहकर यह कार्य किया जाए। इसके साथ ही केरवा बाँध पर हुई बैठक में निर्धारित किए गए मंत्री समूह भी विषयवार बैठकों का आयोजन करें। सभी विभाग पूरी दक्षता से कार्य करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रि–परिषद के सदस्यों को बताया कि आज प्रदेश में सौ नये दीनदयाल रसोई केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की 326 करोड़ 25 लाख से अधिक की राशि उनके खातों में जमा की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम प्रदेश के विकास के संकल्प को पूर्ण करें। टीम भावना से किए गए कार्य के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को सभी मंत्रीगण ने आज विधानसभा में दिए गए प्रभावी उद्बोधन के लिए बधाई भी दी। साथ ही प्रदेश के नागरिकों के कल्याण की दिशा में आज शुरू की गई 100 दीनदयाल रसोई और छात्रवृत्ति की राशि के अंतरण के दो कार्यक्रम संपन्न होने के लिए भी मुख्यमंत्री को बधाई दी गई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 20 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर किये 400 करोड़ रु.

बुन्देलखण्ड की धरती तक पहुँचेगा केन–बेतवा का पानी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 20 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 400 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में ट्रान्सफर की। दमोह जिला मुख्यालय पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनायेंगे। विकास में मध्यप्रदेश को पीछे नहीं रहने देंगे। हमारी सरकार किसानों, गरीबों, माताओं और बहनों के लिये काम करने वाली सरकार है। कोरोना काल से अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत हमने करोड़ों रुपये की राशि किसानों के खातों में भेजी है। आने वाले 15 दिनों में हम पिछले साल खराब हुई फसलों की राहत राशि के तौर पर 1500 करोड़ रुपये की राहत भी प्रभावित किसानों के खातों में ट्रान्सफर करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों की उन्नति एवं समृद्धि के लिये कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी प्रदेश के किसानों से गेहूँ, चने का दाना–दाना खरीदा है। इस साल भी खरीदेंगे। दमोह जिले में जिन किसानों का पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है, उनके लिये पंजीयन की अवधि बढ़ाई जाएगी। कार्यक्रम में केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद पटेल, खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन अध्यक्ष श्री राहुल सिंह और पूर्व मंत्री श्री जयंत मलैया ने भी संबोधित किया।

किसानों से किया संवाद

मुख्यमंत्री किसान–कल्याण योजना के तहत आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना, देवास, शिवपुरी, शाजापुर और सिवनी जिले के किसानों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने इस दौरान किसानों से योजना का फीडबैक लिया। साथ ही उनकी समस्यायें भी सुनी और उनके निराकरण के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

दमोह को दी 482 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह जिले को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 482 करोड़ रूपये से अधिक लागत के कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इसमें महत्वूपर्ण रुप से 325 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन शामिल है।

दमोह के खनिज संसाधनों का दोहन कर स्थापित करेंगे उद्योग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दमोह का सर्वांगीण विकास होगा। दमोह जिले में उपलब्ध खनिज साधनों का दोहन का हम लघु, मध्यम और बड़े उद्योग भी स्थापित करेंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। उन्होंने दमोह जिले में सिंचाई के लिये किये जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दमोह शहर के लिये चल रही पेयजल योजना के कार्य को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दमोह के सर्वांगीण विकास के लिये सभी महत्वपूर्ण विकास कार्य कराये जायेंगे।

बुन्देलखण्ड की धरती तक पहुँचेगा केन–बेतवा का पानी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि लंबे समय से चल रहे केन–बेतवा का विवाद निपट चुका है। हम शीघ्र ही प्रधानमंत्री से मिलकर इस विषय पर चर्चा करेंगे और शीघ्र ही इन नदियों के पानी को बुन्देलखण्ड की धरती तक पहुँचायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दमोह के 446 गाँवों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल के माध्यम से जल पहुँचाने की घोषणा की।

गरीबों के राशन को खुर्दबुर्द करने वालों को भेजें जेल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिले के प्रत्येक पात्र हितग्राही को पात्रता पर्ची जारी करें। कोई भी गरीब इससे न छूटे। यह कलेक्टर की जिम्मेदारी है। जिन पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची बने, उन्हें राशन मिले, यह भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के राशन को खुर्दबुर्द करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हथकड़ी लगवायें और जेल भिजवायें। गड़बड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा न जाए।

महिलाओं को करेंगे आर्थिक रुप से सशक्त

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सशक्त कदम उठाये जा रहे है। हर माह अलग–अलग स्व–सहायता समूहों के खाते में 150 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा रही है। अब हमारी समूह की महिलायें गणवेश भी बनायेंगी। बहनों की आमदनी बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि गणवेश निर्माण कार्य में समूह की बहनें ही काम करें, कोई ठेकेदार न घुसे।

एफआईआर काफी नहीं, संपत्ति कुर्क कर प्रभावितों को दिलायें राशि

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रलोभन देकर अवैध रुप से धन एकत्र करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि हमने अब तक ऐसी कई कंपनियों की संपत्ति जप्त कर नीलाम की हैं और करोड़ों रुपये का भुगतान प्रभावित लोगों को कराया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आप चिन्ता न करें, ऐसी धोखाधड़ी करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। मध्यप्रदेश की धरती पर किसी माफिया को नहीं छोड़ा जायेगा, यह मेरा संकल्प है। दमोह में भी ऐसी चिटफंड कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दिये गये।

गरीबों की ताकत है संबल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के खजाने पर पहला हक हमारे गरीब भाईयों और बहनों का है। हमने संबल योजना फिर से प्रारंभ की है। यह गरीबों की ताकत और उनका संबल है, जिसके तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिलेगा।

प्रत्येक पात्र का बनें आयुष्मान कार्ड

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंच से जिला कलेक्टर से आयुष्मान भारत योजना के बनने वाले कार्डों की जानकारी ली। उन्होने कहा कि प्रत्येक पात्र गरीबों का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। कोई भी पात्र गरीब इससे वंचित नहीं होना चाहिये। हमने अब तक 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनवाये हैं। इस कार्ड के माध्यम से चिन्हित निजी चिकित्सालयों में भी 5 लाख रुपये तक का उपचार हमारे पात्र भाईयों और बहनों को मिल सकेगा।

नहीं चलेगी माफियागिरी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने का अभियान चल रहा है। किसी की माफियागिरी नहीं चलेगी। जो साफ काम नहीं करेगा, उस पर कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री ने माफियाओं के विरूद्ध होने वाली कार्यवाही सतत् रुप से जारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

हितग्राहियों को बांटे हितलाभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न सिंह, विधायक सर्वश्री श्री पी.एल. तन्तुवाय, धमेन्द्र सिंह लोधी, श्रीमती रामबाई सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शिवचरण पटेल, पूर्व मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया पूर्व सांसद चन्द्रभान सिंह सहित जन–प्रतिनिधि उपस्थित थे।

वन्य प्राणियों द्वारा पहुंचाई क्षति भी प्राकृतिक आपदा घोषित

भोपाल। राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार वन्य प्राणियों द्वारा मकान में पहुँचाई गई क्षति को भी प्राकृतिक प्रकोपो से होने वाली हानि की श्रेणी में शामिल किया गया है। विगत दिनों मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्राकृतिक प्रकोपो से होने वाली हानि के वर्तमान में प्रावधानित मानदंडों में संशोधन करते हुए अब किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण या वन्य प्राणियों द्वारा मकान पूर्ण रूप से नष्ट किया गया हो अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ हो तो उसे भी आर्थक अनुदान सहायता दी जा सकेगी।

इसके साथ ही प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुघर्टना के साथ वन्य प्राणियों द्वारा पीड़ित परिवार के कपड़े, खाद्यान्न एवं बर्तनों की हानि के लिए प्रति परिवार 5 हजार रूपये आर्थिक अनुदान के रूप में तथा 50 कि.ग्रा. खाद्यान्न (गेंहूँ/चावल) एवं पांच ली. केरोसीन तात्कालिक सहायता के रूप में दिये जायेंगे। इसके साथ अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में एसडी आरएफ (स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फंड) से राहत राशि व्यय में ऐसे मद भी शामिल किए गए हैं, जिनके विषय में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। राज्य शासन द्वारा लिए आदेशानुसार प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के मामलों में अब देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल क्षति हुई हो तो भी अनुदान सहायता नष्ट हुई फसल के मूल्य के बराबर देय होगी तथा प्रत्येक खाते हेतु सभी फसलों के मामले में देय राशि 5 हजार से कम नहीं होगी।

सर्वाधिक अल्पावधि में फसल ऋण वितरण करने पर किया पुरस्कृत

खरगोन। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खरगोन को नाबार्ड द्वारा राज्य स्तर पर गत वर्ष किसानों को सर्वाधिक अल्पावधि फसल ऋण वितरण करने पर पुरस्कृत किया है। यह पुरस्कार नाबार्ड के राज्य ऋण संगोष्ठी कार्यक्रम में बैंक के एमडी ए.के. जैन को वित्त विभाग के संचालक गणेश शंकर मिश्रा एवं नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती पी.एस. राजी गेन ने प्रदान किया। बैंक को पुरूस्कार प्राप्त होने पर बैंक प्रशासक संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर श्री जगदीश कनोज उप आयुक्त सहकारिता जिला खरगोन श्री विनोद सिंह द्वारा शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर बैंक से जुडे कृषकों, अमानतदारों एवं संगठनों द्वारा भी शुभकामनाएं दी है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है, कि जिला सहकारी बैंक खरगोन कृषकों को अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही वृहद स्तर पर अन्य बैंकिंग व्यवसाय भी कर रही है। अपने व्यवसाय के अंतर्गत अकृषि ऋण योजनाओं में विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण दे रही है। बैंक की 69 शाखाएं सीबीएस प्लेटफार्म पर कार्यरत होकर अपने ग्राहकों को एटीएम सुविधा, मोबाईल बैकिंग, आरटीजीएस/एनईएफटी, लॉकर्स सुविधा सहित अन्य कई बैकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही है। साथ ही अपने ग्राहकों का हित संरक्षण करते हुए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी दे रही है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन द्वारा प्रदेश की

सहकारी बैंकों में सर्वाधिक ऋण वितरण एवं अमानतें प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है, इसी वजह से प्रदेश में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है। विगत वर्ष 2013–14 में जिला बैंक खरगोन को नेप्सकाब से ''राष्ट्रीय स्तर'' पर सर्वोत्तम कार्य–निष्पादन का पुरूस्कार प्राप्त हुआ था। हाल ही में नाबार्ड द्वारा किए गए निरीक्षण में बैक को सर्वोत्तम कार्य–निष्पादन वाली बैंकों की श्रेणी में रखते हुए ''ए'' ग्रेड प्रदान किया गया है।

जिला सहकारी बैंक खरगोन की अमानतों की ब्याजदरें प्रतिस्पर्धी होकर अन्य बैंकों की तुलना में सर्वाधिक रहती है, वही वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याजदर की व्यवस्था रखी गई है। ग्राहकों एवं अमानतदारों को आवश्यकता होने पर तत्काल भुगतान की व्यवस्था है। इसलिए ग्राहकों का बैंक के प्रति पूर्ण विश्वास बना हुआ है। यही बैंक की सबसे बडी पूँजी है, वैसे बैंक में डिपाजिट के रूप में ग्राहकों का लगभग रू. 1598.84 करोड जमा है। यह हमारी उपलब्धि है कि हमने खरगोन एवं बडवानी जिले में लगभग 2 लाख 60 हजार किसानों को करीब 1953.54 करोड का केसीसी ऋण उपलब्ध कराया है। हमारा सदैव यह प्रयास रहता है कि बैंक के प्रति ग्राहकों का विश्वास बना रहे। बैंक अपने ग्राहकों एवं अमानतदारों को बेहतर सुविधा देने के लिए कृत–संकल्पित है।

आत्म निर्भर भारत एवं आत्म निर्भर मध्यप्रदेश योजनांतर्गत पैक्स के प्रबंधकों एवं सहायक प्रबंधकों का प्रशिक्षण

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में माह मार्च 2021 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधकों के लिए आत्मनिर्भर भारत एवं मध्यप्रदेश योजनान्तर्गत पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया । दिनांक 1 से लेकर 10 मार्च 2021 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण के कुल तीन सत्र आयोजित किए गए। प्रशिक्षण का प्रमुख उददेश्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुसेवा केन्द्र के रूप मे विकसित कर आत्मनिर्भर

बनाने की दिशा में अग्रसर करना था।

आत्मनिर्भर भारत/मध्यप्रदेश योजनान्तर्गत पैक्स को आत्मनिर्भर एवं बहुसेवा केन्द्र बनाने हेतु शासन एवं नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्रता रखने वाली विभिन्न पैक्स को वेयर हाउस निर्माण,ग्रेडिंग सार्टिंग यूनिट लगाने, कृषि सूचना एवं किसान सुविधा केन्द्र बनाने हेतु चयनित किया जाकर आवश्यक संसाधन एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाना है। डी पी आर में उल्लेखित सभी बिंदुओं पर जानकारी एवं मार्गदर्शन तथा शंका समाधान हेतु प्रशिक्षण का आयोजन राज्य सहकारी संघ भोपाल द्वारा किया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा किया गया । श्री रंजन ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उददेश्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डी.पी. आर पर विस्तृत चर्चा एवं विश्लेषण अंतर्गत – बिजनेस प्लान, लक्ष्यपूर्ति, आय सृजन, पुनर्भुगतान आदि पर जानकारी नाबार्ड के सहायक प्रबंधक श्री विवेक गुप्ता द्वारा दी गई। आयुक्त सहकारिता द्वारा जारी परियोजना नियमावली एवं मार्गदर्शिका संचालन पर चर्चा श्री प्रेम द्विवेदी, उपायुक्त द्वारा की गई। ग्रेडिंग सॉर्टिंग यूनिट हेतु मशीनों का चयन एवं संचालन पर व्याख्यान डॉ सुबीर चक्रवर्ती एवं डॉ दिलीप पवांर वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। वेयर हाउस का निर्माण एवं उसमें ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य, भण्डारण की वैज्ञानिक विधियॉ पर जानकारी श्री एच.एम.त्रिपाठी, से.नि. भण्डारण निरीक्षण अधिकारी एवं क्वालिटी पैरामीटर ट्रेडमार्क, एगमार्क, आई.एस.ओ. सार्टिफिकेशन, एपीडा के गुणवत्ता मापदंड, पैकेजिंग, फारवर्ड लिंकेज पर जानकारी डा. पुरूषोत्तम शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्वालिटी कंट्रोल लबोरेटरी द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त कृषि सूचना एवं किसान सुविधा केन्द्र का संचालन एवं प्रबंधन, उत्पाद में मूल्य संवर्धन एवं विक्रय, नेतृत्व विकास, संप्रेषण कला प्रबंधकीय कौशल, कर्मचारियों की व्यवस्था, पैक्स मैनेजर की भूमिका आदि विषयों पर श्री अभय गोखले, पूर्व ए जी एम अपेक्स बैंक, भोपाल श्री पी.के. एस. परिहार, सेवा निवृत्त महा प्रबंधक, अपेक्स बैंक श्री कपिल पागनीस, कार्यकारी निदेशक आदित्य विजन फॉर डेवलपमेंट श्रीमती रश्मि गोलिया कार्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा रोल प्ले, प्रस्तुतिकरण, समूह चर्चा, व्याख्यान के माध्यम से प्रकाश डाला गया। दिनांक 1.3.2021 से प्रारंभ प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में इंदौर, उज्जैन, विदिशा, बडवानी, नरसिंहपुर जिलों के कुल 26 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। दिनांक 4.3.2021 से प्रारंभ द्वितीय सत्र में खरगोन, उमरिया, भोपाल, धार राजगढ़, नरसिंहपुर एवं इंदौर जिलों के कुल 33 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। दिनांक 8.3.2021 से प्रारंभ तृतीय सत्र में छतरपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, रीवा, सीहोर,

सिवनी, धार जिलों के कुल 26 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन संघ के ओ.एस.डी. श्री संजय कुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समन्वय श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य, श्रीमती रेखा पिप्पल व्याख्याता श्री संतोष येड़े राज्य समन्वयक एवं श्री विनोद कुशवाह, सहायक द्वारा किया गया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।